

नीट परीक्षा

केंद्र सरकार ने नीट यूजी 2024 के एक हजार 5 सौ 63 विद्यार्थियों को एम.बी.बी.एस, बी.डी.एस और अन्य पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने के लिए अतिरिक्त अंक देने के फैसले को रद्द कर दिया है। केन्द्र सरकार ने इस संबंध में आज सुप्रीम कोर्ट में सूचना दी। न्यायाधीश न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ को केंद्र तथा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की परिषद ने बताया कि जिन विद्यार्थियों को अतिरिक्त अंक मिले थे उनके पास 23 जून को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प रहेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा कि पहले से घोषित काउंसलिंग कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि दोबारा से होने वाली परीक्षा के परिणाम 30 जून तक घोषित कर दिए जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने आज इस बात को दोहराया कि वह नीट यूजी 2024 प्रवेश काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाएगा। वहीं सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय पात्रता-प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी 2024 में प्रश्नपत्र लीक होने का कोई सबूत नहीं मिला है। सरकार ने परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी के आरोपों से भी इनकार किया है।

समितियां

विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पटानिया ने विधानसभा की प्रक्रिया व कार्यसंचालन नियमावली के अनुसरण में वर्ष 2024-25 के लिए गठित सदन की समितियों में आंशिक परिवर्तन किया है। इन समितियों में सभापति और सदस्यों को नए सिरे से नामांकित किया गया है। जिन समितियों में परिवर्तन किया गया है उनमें लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति, कल्याण समिति, स्थानीय निधि लेखा समिति, अधीनस्थ विधायन समिति, जन प्रशासन समिति, मानव विकास समिति, सामान्य विकास समिति, ग्रामीण नियोजन समिति, विशेषाधिकार समिति, सदस्य सुविधा समिति, कार्य सलाहकार समिति, नियम समिति, आचार संहिता समिति, पुस्तकालय अनुसंधान व संदर्भ समिति, ई-गवर्नेंस व सामान्य प्रायोजनों संबंधी समिति, प्रोटोकॉल मानदण्डों के उल्लंघन और अवमाननापूर्ण व्यवहार समितियां शामिल हैं।

बिंदल

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के पास गृह विभाग होने के बावजूद राज्य में कानून व्यवस्था खस्ताहाल है। उन्होंने सिरमौर और चम्बा जिलों में पुलिस अफसरों और पुलिस जवान के साथ घटित घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इस तरह के मामलों से प्रदेश पुलिस की छवि धूमिल हो रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में बंदूक की नोक पर लोगों का अपहरण कर फिरौती मांगी जा रही है। बिंदल ने ये भी कहा कि राज्य में खनन माफिया भी बेलगाम है और पूरा प्रदेश

अशांत तथा असुरक्षित हो गया है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था के मामले में इस समय प्रदेश राम भरोसे है। बिंदल ने मुख्यमंत्री से कानून व्यवस्था की ओर तुरंत ध्यान देने की मांग की है।

कांग्रेस

मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने आरोप लगाया है कि राजनीतिक महत्वकांक्षा न पूरी होने के कारण भाजपा नेता बौखलाहट में है। नरेश चौहान ने आज शिमला में एक बयान में कहा कि भाजपा नेता मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्तियों को लेकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये नियुक्तियां संवैधानिक है और मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में भाजपा को इन नियुक्तियों को असंवैधानिक करार देना गैर कानूनी है। नरेश चौहान ने आरोप लगाया कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर अपनी कुर्सी बचाने के लिए सरकार गिराने के दावे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उपचुनाव के बाद प्रदेश सरकार और मजबूत हुई है। ऐसे में जयराम ठाकुर को अपनी सरकार बनाने की सम्भावनाओं के लिए वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का इंतजार करना होगा। उन्होंने कहा कि वास्तव में जयराम ठाकुर और राजीव बिंदल अपना अस्तित्व बचाए रखने की लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि अनुराग ठाकुर को केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में जगह नहीं मिली है और वे प्रदेश में अपना राजनीतिक भविष्य तलाशने लगे हैं।

प्रभारी

प्रदेश कांग्रेस ने 10 जुलाई को होने वाले 3 विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। पार्टी महासचिव रजनीश किमटा ने आज शिमला में कहा कि देहरा विधानसभा सीट के लिए कृषि मंत्री चौधरी चन्द्र कुमार नालागढ़ विधानसभा सीट के लिए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और हमीरपुर विधानसभा सीट के लिए तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी पार्टी प्रभारी होंगे। किमटा ने कहा कि पार्टी इन उपचुनावों के लिए पूरी तरह तैयार है और एकजुटता के साथ धनबल का सामना करेगी।